it will help us promote self-reliance programmes which the Minister of Planning and others in the Government want to achieve during the next Five Year Plan period.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: As far as the consortium commitments are concerned, normally some pledges are made in the course of the discussions but ultimately when it comes to disbursements or sanctions it is done in a bilateral manner at Government level; certain agreements are reached. Of course the other part of the question refers to our general strategy on taking foreign aid. We have explained it before; our idea is to see that our net aid reaches zero at the end of the Fifth Plan and it is on that basis that we will be proceeding this year.

नागरिक उड्डयन मंडल (सी० ए० बी०) के प्रवंतन ब्यूरो द्वारा एयर इंडिया के विरुद्ध युक्क किराया टिकट श्रधिक श्रायु के यात्रियों को बेचने का श्रारोप

\*1068. भी शिव कुमार शास्त्री :† श्री भगीरथ भंवर :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या नागरिक उडड्यन मण्डल (सी॰ ए॰ बी॰) के प्रवर्तन ब्यूरो ने एयर इण्डिया पर वह ग्रारोप लगाया है कि उसने गैर-कानूनी ढंग से युवक किराया टिकट ग्रधिक ग्रायु के लोगों को बेचे हैं:
- (ख) क्या एयर इण्डिया के विरुद्ध यह भी आयरोप है कि उसने लंदन और न्यूयार्क के बीच काका के लिये 93 टिकट कम मूल्य पर बेचे हैं?
- (ग) क्या यह घरोप केवल एयर इण्डिया कर ही लगाया गया है; घीर
- (भ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं भीर सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH):
(a) and (b). The U.S., Civil Aeronautics Board has alleged that Air India infringed in certain ticketing regulations and wrongly agreed to pay some extra commission to a travel agency in order to persuade passengers to fly Air India. The complaint itself,

however, indicates that this extra commission was not in fact paid.

- (c) The information is not available.
- (d) Air India is preparing its reply to the complaint and its stand is that it has not violated the Federal Aviation Act.

श्री शिव कुमार शास्त्रीः श्रीमन्, शिकायत के ढंग से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रायः इस प्रकाइ के आरोप-प्रत्यारोप नागरिक उड्डयन की ओर से विभिन्न विमान सेवाओं पर लगाये जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं—क्या इस प्रकार का प्रयत्न किया गया है कि सब के लिये एक प्रकार के नियम निर्धारित किये जायें और सब की याती बिना किसी संघर्ष और खींचातानी के प्राप्त हो सकें? यदि प्रयत्न किया गया है तो उस का क्या परिणाम निकला ?

डा॰ कर्ण सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, हर एक देश की अपनी अपनी सिविल एवियेशन अथारिटीज होती हैं, वे जब भी समझती हैं कि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो वे उस के प्रति अपनी कार्य-वाही करती हैं—ऐसा सारे संसार में होता है।

जहां तक फेग्नर्स का प्रश्न है—इयाटा प्रयत्न कर रहा है कि फेग्नर्स के सम्बन्ध में जो संघर्ष है वह दूर हो ग्रीर वह प्रयत्न ग्रभी जारी है।

श्री शिव कुमार शास्त्रीः : ग्राप के उत्तर से एक ग्रंश स्पष्ट नहीं होता । ग्राप ने उस एजेन्सी को जिस के द्वारा कुछ मुसाफिर लाने के लिये यत्न किया गया था, पैसा नहीं दिया, शायद बातचीत की गई थी तो तो वह ग्रंश भी स्पष्ट होता चाहिये।

दूसरी बात में यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में ग्राप के विमानों की जो क्षमता है, उतने यात्री ग्राप को मिल जाते हैं? यदि नहीं मिलते तो कितनी कमी रह जाती है ग्रौर उस से कितनी क्षति होती है?

डा० कर्ण सिंह: प्रध्यक्ष महोदय, यह तो एक विशेष केस है जो सिविल एरोनौटिक्स बोर्ड के सामने है। एग्नर इण्डिया का इस सम्बन्ध में जो प्रपना डिफेंस है, वह उसको बना रहा है भौर जो उस को कहना होगा, वह कहेगा।

14

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है वह मुझे समझ में नहीं ग्राया । हर विमान सेवा का यह वत्न होता है कि उस के विमान परे भरे हए जायें। एग्नर इंडिया का सारे संसार में इस समय भ्रच्छा इमेज है।

श्री शिव कुमार शास्त्री: मान लीजिये ग्राप के एक विमान में 100 यात्रि जा सकते हैं-यत्न करने पर भी क्या उतने यात्री उपलब्ध हो जाते हैं या कछ स्थान खाली जाते हैं।

डा॰ कर्ण सिंह: सेंकड़ों फुलाइट्स है कुछ भरी हुई जाती है, कुछ ग्राधी जाती है-यह कहना सम्भव नहीं है। हम यत्न करते 🕏 कि सभी भरी हुई जायें।

SHRI PRABODH CHANDRA: Since the hon. Minister has just now stated that the Air India is now making its defence, was it not very discourteous on the part of the Association to go to the Press and vilify Air India's great service when the case has not been finalised by the competent Court?

DR. KARAN SINGH: I do not know who went to the Press actually. But, indeed this is one of the occupational hazards. When the case is pending and when someone goes to the press, I must, in order to set the re-cord straight, say here that Air India has got a very good image in the world.

मुझे एक शेर याद म्राया -

हम बाह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, बह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

## सफाई कर्मचारियों का जीवन बीमा

\*1069. भी शंकर वयाल सिंह : । श्रीमती साबिब्री श्याम :

क्या किल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक भप्रैल, 1973 के "नवभारत प्रकाशित इस भागय के समाचार की भोर दिलाया गया है कि भारतीय जीवन निगम सफाई कर्मचारियों का बीमा नहीं करता क्योंकि वे सरलता से रोगग्रस्त हो सकते हैं: भीर

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध को के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जी हां।

(ख) जिन प्रस्तावों में म्रत्यधिक जोखिम ग्रस्त होती है, जैसे नालियों के मोखों से निकलने वाली जहरीली गैस स्रौर भूमिगत स्रन्य दूर्घटनास्रों से सम्बन्धित जोविमों के मामलों को छोड कर. ग्रन्य मामलों में जीवन बीमा निगम, बीमे की ध्रधिकांश योजनाम्रों के मन्तर्गत झाडकशों भीर सफाई कर्मचारियों के जीवन बीमे के प्रस्ताब सामान्य दरों पर स्वीकार करता है।

श्रीमती सावित्री श्याम : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना हंकि यह संविधान की या एल**्याई**०सी**० की** किस धारा के प्रन्तर्गत कि उन के साथ ऐसा डिस्कीमिनेशन किया जाय, जो ग्रधिक रिस्क में काम करे. जोखम में काम करें, चाहे मेन होल में स्बाएल उठाये-उन को सोशल सिक्योरिटी प्रदान न की जाय ?

भीमती सुशीला रोहतगीः : मान्यवर, जैसा कि उत्तर से स्पष्ट है कि इस तरह की कोई डिस्की-मिनेशन नहीं है भौर सभी सफाई कर्मचारियों को उसी स्टेण्डर्ड रेट माफ़ प्रीमियम पर इन्गोरेंस किया जाता है। लेकिन जहां ज्यादा जोखिम है, जैसे जमीन के नीचे मेन होल्ज हैं, भ्रण्डर-ग्राउण्ड ड़ेनेज है, जहां जहरीली गैस होती है, वहां सुरक्षा के प्रयास किये जाते हैं। जैसे बम्बई कारपोरेशन ने उनके लिये एक विशेष स्क्वेड बनाया हुआ है, जहां समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। वहां यह भी देखा गया है कि पिछले पांच वर्षी के मन्दर इस प्रकार की कोई ऐसी ट्रैंड्डिना नहीं हुई है, वहां जोखिम का काम होने पर भी इस प्रकार का कोई डिस्कीमिनेशन नहीं हुआ है, सामान्य दरों पर इंशोरेंस हमा है।

जहां तक माननीय सदस्या ने कहा कि जहां ज्यादा जोखिम होता है तो वहां मेरिट पर यह चीज देखी जाती है।